time lag for exporters to react to the far-reaching reforms in trade policy, no specific target for 1991-92 has been finalised.

(b) During the first six months of 1991-92 as compared to the corresponding period of 1990-91, exports to RPA countries declined by 54% while exports to GCA countries increased by 5.4% month wise figures are:—

(US S Million)

Month		1990-91	1991-92	% Growth
April	GCA	1131	1291	14.1
	RPA	293	197	−32.8
May	GCA	1193	1171	−1.8
	RPA	316	121	−61.7
June	GCA	1040	1067	2.6
	RPA	288	158	−45.1
July	GCA	1139	1200	5.4
	RPA	303	101	−66.7
Aug.	GCA	1192	1257	5.5
	RPA	254	86	−66.1
Sep.	GCA	1160	1280	10.3
	RPA	279	132	−52.7

(c) No sector-wise targets have been finalised, due to the uncertainties relating to the development in the global economy, exports to USSR on account of difficulties being experienced by the USSR to supply necessary imports due to dislocation in the Soviet Union and the time lag for exporters to react to the far reaching reforms in trade policy announced in July and August, 1991.

(d) The Government introduced a package of trade policy reforms aimed at strengthening of exports incentives eliminating substantial volume of import licensing and optimal import compression. REP licences have been replaced by a new instrument named Eximscrips. These will be the means of obtaining access to certain categories of imports of raw material components and spares. The system of advance licensing as an instrument of export promotion has also been strengthened. Government has decided to allow established exporters to open foreign currency accounts in approved banks and allow exporters to raise external credits, pay for export related imports from such accounts and credit export proceeds to such accounts. Besides, Government have taken other steps which include reducing controls through licencing, simplification of procedures for exports, activisation of Board of Trade, bilateral discussion with selected countries, interaction with national organisations of trade and industry etc.

जेरॉक्स मशीनों की बिक्री के एकाधिकार

2631. **मौलाना ओबैदुल्ला खान आज़मी:** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने मैसर्स मोदी जेरॉक्स को सरकारी विभागों को अपनी जेरॉक्स मशीनें बिक्री करने के एकाधिकार दे दिये हैं;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) सरकारी विभागों को ये जेरॉक्स मशीनें वर्तमान में किन शर्तों पर उपलब्ध करायी जा रही हैं;

(घ) क्या यह भी सच है कि मोदी जेरॉक्स के साथ की गई यह व्यवस्था अलाभकर है और सरकार को इस सौदे में प्रति वर्ष लाखों रुपये का घाटा हो रहा है और यह कि जेरॉक्स मशीनें खुले बाजार में कहीं कम मूल्य पर उपलब्ध हैं;

(ङ) यदि हां, तो उपर्युक्त फर्म के साथ की गयी इस व्यवस्था का औचित्य क्या है;

(च) क्या सरकार इस मामले की उच्च स्तरीय जांच करायेगी; और

(छ) सरकार इस संबंध में खुली प्रतियोगिता को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाने का विचार रखती है?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद): (क) और (ख) मैसर्स मोदी जेंक्स को सरकारी विभागों को अपनी जेरॉक्स मशीनें बिक्री करने के एकाधिकार देने के संबंध में पूर्ति विभाग द्वारा कोई आदेश जारी नहीं किया गया है।

(ग) से (छ) फोटोकॉपियिंग मशीनों की अधिप्राप्ति पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय द्वारा किए जाने का कार्य वर्ष 1985 में विकेन्द्रित कर दिया गया था तथा केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों/विभागों को अपनी मांग हेतु इन मशीनों की खरीद सीधे करने के लिए अधिकृत कर दिया गया है।

आयुर्वेदिक औषधियों का निर्यात

2632. **श्री रणजीत सिंह:**
डा० जिनेन्द्र कुमार जैन:

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 25 अक्टूबर, 1991 को दैनिक "ट्रिब्यून" में प्रकाशित "डेवलप्ड नेशन्स टेकिंग टू आयुर्वेदा" शीर्षक समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि देश से देशी जड़ी-बूटियों और उनसे निर्मित औषधियों के निर्यात में लगातार वृद्धि हो रही है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार देश और विदेश में आयुर्वेदिक शोध कार्य को बढ़ावा देने और शोध कार्य के परिणामों का लाभ आम आदमी तक पहुंचाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कोई कार्य-योजना कार्यान्वित करने का विचार रखती है;

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्): (क) और (ख) जी हां।

(ग) और (घ) केन्द्रीय आयुर्वेद एवं सिद्ध औषधि अनुसंधान परिषद् देश के विभिन्न भागों में अपनी अनुसंधान परियोजनाओं के माध्यम से अनुसंधान संबंधी अध्ययन कर रही है।

Four Points Plan to Increase Export

2633. SHRI JAGADISH JANI: Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) whether Government have proposed a four points plan to the states to increase their export;

(b) if so, what are the details of this plan; and

(c) the reaction of the State Governments thereto?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI P. CHIDAMBARAM): (a) and (b) The Government of India has made the following suggestions to the State Governments to boost their exports:—

(1) Create a nodal point in the State Secretariat and appoint a nodal officer to deal with exports;

(2) Exempt exports from State fiscal levies;

(3) Set up an Apex level Body under the Chairmanship of Chief Minister for policy formulation;

(4) Set up Board of Trade in the State to ensure continuous dialogue with trade and industry;

(5) Set up an Export House as a joint venture with a private sector partner.

(c) The reaction of the States, received so far, has been positive.

Payment of CCS and Supplementary CCS in Lieu of Duty Drawback

2634. SHRI SUBRAMANIAN SWAMY: Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) whether it is fact that due to lack of budget allocation, the payment of CCS and Supplementary CCS in lieu of Duty Drawback has not been made since July, 1991;

(b) if so, the reasons therefor;

(c) whether it is fact that payment of Supplementary CCS (in lieu of duty draw-back) to deemed exporters is actually a refund;

(d) if so, why budget allocation is